



सुशासन | विकास | रोजगार

डबल इंजन की सरकार





सुदृढ़ कानून व्यवस्था



- ❖ प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिक बेहतर बनाने के लिए अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध **जीरो टॉलरेंस** की नीति जारी।
- ❖ प्रदेश में लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज में पुलिस कमिशनरेट व्यवस्था लागू।
- ❖ वीमेन पावर लाइन 1090, G.R.P., फायर सर्विस, महिला हेल्प लाइन 181 सेवा का एकीकरण।
- ❖ प्रत्येक जिले में एण्टी रोमियो स्कवायड का गठन। 3,90,64,523 व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 1,44,06,253 व्यक्तियों को चेतावनी एवं 32,077 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही।
- ❖ महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन 1090 का गठन। प्रत्येक जनपद में महिला थाना के अतिरिक्त एक अन्य थाने में महिला थानाध्यक्ष की तैनाती।
- ❖ महिला एवं बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान (98.20 प्रतिशत निस्तारण दर)। 03 महिला P.A.C. बटालियन का गठन।



- ❖ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नामक नये सुरक्षा बल का गठन ।
- ❖ ई-प्रॉसीक्यूशन प्रणाली के उपयोग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर ।
- ❖ दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही में अब तक 217 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 7,799 घायल । 28,085 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिनमें 19,955 इनामी अपराधी हैं । 78,977 अपराधियों के विरुद्ध जैजिस्टर अधिनियम तथा 924 अपराधियों के विरुद्ध एन०एस०ए० की कार्यवाही । जैजिस्टर अधिनियम के अंतर्गत 140 अरब 90 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक लागत मूल्य की चल/अचल अवैध सम्पत्तियों का जब्तकरण ।
- ❖ प्रदेश स्तर पर चिन्हित 68 माफिया व उनके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों में कुल 1,391 के विरुद्ध 782 अभियोग पंजीकृत तथा 611 की गिरफ्तारी, 359 शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही, 18 के विरुद्ध NSA, 752 के विरुद्ध जैजिस्टर एक्ट, माफिया एवं अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित रु० 4,067 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति जब्त ।
- ❖ 01 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2024 तक महिलाओं/नाबालिगों के विरुद्ध हुए अपराधों में 6,792 प्रकरणों में अभियुक्तों को सजा दिलाई गई । पॉक्सो अधिनियम के अपराधों में 16 प्रकरणों में मृत्युदण्ड, 429 प्रकरणों में आजीवन कारावास, 1,633 प्रकरणों में 10 वर्ष से अधिक सजा व 2,057 प्रकरणों में 10 वर्ष से कम सजा से दण्डित कराया गया ।
- ❖ प्रदेश में 126 नये थाने, 86 नई चौकियां, 04 जल पुलिस चौकी, 78 महिला पुलिस चौकी परामर्श, 75 विद्युत निरोधक पुलिस थाना, 10 सतर्कता अधिष्ठान थाना, 04 आर्थिक अपराध इकाई थाने, 06 यूपीएसएसएफ की स्थापना, 75 साइबर क्राइम थाना व 06 नये नॉरकोटिक्स थाने की स्थापना ।



- ❖ मानव तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 75 एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों में परिवर्तित।
- ❖ 1 लाख 55 हजार 855 पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती। 15,130 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए 10,378 महिला बीटों का आवंटन।
- ❖ धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की ध्वनि निर्धारित मानक के अनुरूप न पाये जाने पर 1,08,037 लाउड स्पीकर हटवाये गये तथा 1,53,417 लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानक के अनुसार कम करायी गयी।
- ❖ महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत 314 महिला P R V की उपलब्धता।
- ❖ लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, गण्डा एवं मुरादाबाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्रियाशील।
- ❖ नवीन संशोधित जेल मैनुअल- 2022 का प्रख्यापन।
- ❖ ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत कुल 11,48,192 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन। इसके माध्यम से प्रदेश में हत्या, डकैती, अपहरण, स्नैचिंग, टप्पेबाजी आदि से सम्बन्धित 1,501 अपराधों का खुलासा कर वैधानिक कार्यवाही की गई।
- ❖ साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाने की स्थापना। 1530 जनपदीय थानों में साइबर सेल का गठन। वर्ष 2017 से अब तक 171.51 करोड़ रु० की धनराशि संबंधित बैंकों में प्रीज/होल्ड करायी गई।



❧ अवस्थापना सुविधाओं का विकास ❧

- ❖ वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित गति से बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विकास।
- ❖ 6 एक्सप्रेस-वे संचालित, 7 विकास के विभिन्न चरणों में।
- ❖ 91.35 किमी. लम्बे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रगति पर।
- ❖ मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी. लम्बे गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य प्रगति पर। 114.650 किमी. बलिया लिंक एक्सप्रेस का निर्माण कार्य प्रारम्भ।
- ❖ चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे तथा जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित।
- ❖ प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क (16,000 किमी से अधिक) है।
- ❖ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी (ग्रेटर नोएडा) में है।
- ❖ उत्तर प्रदेश 05 अन्तरराष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डों के साथ 21 एयरपोर्ट वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर।
- ❖ जेवर, नोएडा में अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन।
- ❖ लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, आगरा और चित्रकूट में 06 नोड पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास। देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका।
- ❖ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में झांसी नोड के अंतर्गत भारत डायनेमिक्स लिमिटेड तथा लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई सहित अब तक 30 हजार करोड़ की निवेश परियोजनाइन प्रक्रियाधीन।



- ❖ देश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन की कार्यवाही शीघ्र।
- ❖ वाराणसी में 100 एकड़ में भारत का पहला फ्रेट विलेज विकसित।
- ❖ भारत के कुल मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में लगभग 45 प्रतिशत योगदान।
- ❖ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे।
- ❖ ग्रेटर नोएडा में आईआईटी जीएनएल, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गोरखपुर में गारमेंट पार्क तथा अनेक प्लैटेड फैक्ट्री परिसरों को विकसित किया जा रहा।
- ❖ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टरप्लान को लागू करने वाला अग्रणी राज्य।
- ❖ लखनऊ में पी.एम. मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास।
- ❖ बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) का गठन। 47 वर्षों के बाद एक नए शहर की स्थापना का मार्ग प्रशस्त। बुन्देलखण्ड के बहुआयामी विकास को गति।
- ❖ 06 औद्योगिक गलियारे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर और 06 औद्योगिक गलियारे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर विकसित किये जा रहे हैं।
- ❖ बरेली के बहेड़ी में मेगा फूड पार्क का विकास।
- ❖ ललितपुर, झाँसी में 1472 एकड़ भूमि पर फार्मा पार्क की स्थापना प्रक्रियाधीन तथा कन्नौज में इत्र पार्क की स्थापना। YEIDA में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना।
- ❖ अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत प्रयाराज और आगरा में 1-1 इंटिग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रक्रियाधीन।
- ❖ अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारम्भ।



निवेश का ड्रीम डेस्टीनेशन

- ❖ वर्ष 2018 में आयोजित यू.पी. इन्वेस्टर्स समिट के फलस्वरूप रु. 4 लाख करोड़ से अधिक की निवेश परियोजनाएं प्रारंभ।
- ❖ यू.पी. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में रु. 39.52 लाख करोड़ से अधिक के एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित। 1.10 करोड़ रोजगार के अवसर होंगे सृजित।
- ❖ फरवरी 2024 में GBC@4 के माध्यम से 10.11 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन प्रारम्भ।
- ❖ उद्योगों की सुगमता के लिए 4674 रेगुलेटरी कम्प्लायंस बर्दन को कम किया गया।
- ❖ प्रदेश में एफडीआई फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन नीति-2023 घोषित।
- ❖ ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विन्डो पोर्टलों में से एक 'निवेश मित्र' का कार्यान्वयन। उद्यमियों को 43 विभागों की 487 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- ❖ उद्यमियों से लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों की 97 प्रतिशत से अधिक निस्तारण दर के साथ 'निवेश मित्र' देश में वर्तमान में कार्यरत सबसे कुशल सिंगल विन्डो पोर्टलों में से एक। अब तक 12.5 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल रूप से जारी की गई हैं।
- ❖ प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात नीति 2020-25 प्रख्यापित। प्रत्येक जिले में निर्यात प्रोत्साहन समिति का गठन।



- ❖ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 218412 लाभार्थी लाभान्वित ।
- ❖ एक जनपद-एक उत्पाद कार्यक्रम (ओ.डी.ओ.पी.) की शुरुआत के बाद से राज्य का निर्यात रु. 88,967 करोड़ से बढ़कर रु. 1.80 लाख करोड़ से अधिक हुआ ।
- ❖ ओ.डी.ओ.पी. वित्त पोषण योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में 3,215 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए रुपये 16536.45 लाख मार्जिन मनी वितरित । 57,880 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध ।
- ❖ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2023-24 एवं चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 5,763 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए रु० 15279.37 लाख की मार्जिन मनी वितरित तथा 46,104 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ।
- ❖ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से 2023-24 में 4,990 लाभार्थियों को 18519.25 लाख मार्जिन मनी वितरित । 39,920 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध ।
- ❖ शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारम्भ ।
- ❖ एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास हेतु एमएसएमई नीति-2022 प्रख्यापित ।
- ❖ प्रदेश में 11 प्लेज पार्को (उन्नाव, सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर देहात. हापुड, सम्भल, झांसी एवं मथुरा) की स्वीकृति ।



नगर विकास

- ❖ 117 नये नगर निकायों का गठन। अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन एवं झाहजहांपुर में देश में सर्वाधिक नये नगर निगम का गठन।
- ❖ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 17 लाख 70 हजार आवासों का निर्माण।
- ❖ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में रेहड़ी/ पटरी/ठेला लगाने वाले 19.72 लाख स्ट्रीट वेन्डर्स को ऋण वितरित।
- ❖ 18 नगरों को सेफ सिटी के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा।
- ❖ स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत 10 स्मार्ट सिटीज में इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर एवं इन्टेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम क्रियाशील।
- ❖ राज्य स्मार्ट सिटी योजना में अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ व झाहजहांपुर का स्मार्ट सिटी के रूप में विकास।
- ❖ स्मार्ट सिटी रैंकिंग में आगरा व वाराणसी प्रथम 10 शहरों में सम्मिलित।
- ❖ अमृत योजना में स्वीकृत 723 परियोजनाओं में से 556 पूर्ण। इसके अन्तर्गत 9.20 लाख घरों में जलापूर्ति एवं 8.60 लाख घरों में सीवरेज संयोजन।
- ❖ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा में मेट्रो रेल सेवा प्रारम्भ। गोरखपुर के लिए डी.पी.आर. तैयार।





- ❖ आकांक्षात्मक जनपद, आकांक्षात्मक विकास खंड के सफल प्रयोग के उपरांत 100 नगरीय निकायों हेतु आकांक्षी नगर योजना का क्रियान्वयन।
- ❖ दिल्ली से मेरठ के बीच देश की पहली रैपिड रेल सेवा 'नमो भारत' का शुभारम्भ।
- ❖ काशी में कैंट रेलवे स्टेशन से गिरजाघर तक रोप-वे सेवा निर्माणाधीन।
- ❖ सभी विकास प्राधिकरणों में भव्य कंवेन्शन सेंटर निर्माणाधीन।
- ❖ नगर निगम लखनऊ व गाजियाबाद द्वारा म्युनिसिपल बॉण्ड जारी।
- ❖ 14 शहरों में 740 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें संचालित।
- ❖ 8,99,634 व्यक्तिगत तथा 69,381 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराते हुए सभी स्थानीय निकायों को ODF घोषित कराने में सफलता।
- ❖ मलिन बस्तियों के पुनर्वास हेतु मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति-2021 लागू।
- ❖ दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत में 431 छोटी नगर पंचायतों/ नगर पालिकाओं में आधारभूत सुविधाओं हेतु रु. 1025 करोड़ निर्गत।
- ❖ सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबन्धित।
- ❖ जनशिकायतों के निवारण हेतु 1533 टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर।
- ❖ जन्म-मृत्यु के पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था। सम्पत्ति कर/म्यूटेशन की ऑनलाइन व्यवस्था।
- ❖ व्यापक जन सहभागिता से 2017-18 से 2024-25 तक 204.65 करोड़ पौध रोपण किया गया।



रोशन प्रदेश

- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे, तहसील मुख्यालय को 22 घण्टे तथा जिला मुख्यालय को 24 घण्टे विद्युत- आपूर्ति।
- ❖ 'पावर फॉर ऑल' के तहत 1 करोड़ 58 लाख घरों का विद्युत संयोजन।
- ❖ 1,21,324 मजरी का विद्युतीकरण।
- ❖ 33/11 के.वी. के 749 नये विद्युत उपकेन्द्र स्थापित एवं 1528 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि।
- ❖ 2x800 मे.वा. ओबरा 'डी' तापीय परियोजना की स्थापना का निर्णय।
- ❖ अयोध्या को सोलर सिटी और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को सोलर एक्सप्रेस-वे के रूप में विकसित करने का प्रयास।
- ❖ 1000 से अधिक आबादी वाले 19031 ग्रामों/मजरी में खुले तार के स्थान पर 51941 किमी. ए.बी. केबल लगाये गये।
- ❖ 8.60 लाख अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर लगाये गये।
- ❖ कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 32009 मेगावाट हुई।
- ❖ स्मार्ट मीटरिंग एवं विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए 'रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम'।
- ❖ 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्रों पर 627 नग कैपेसिटर बैंक स्थापित।
- ❖ निजी नलकूप कनेक्शन देने में डार्क जोन में लगे प्रतिबन्ध को हटाने से 01 लाख किसान लाभान्वित।
- ❖ निजी नलकूप के बिजली बिलों में 100 प्रतिशत की छूट।
- ❖ ट्रांसफार्मर खराब होने पर 24 घंटे में बदलने की व्यवस्था।
- ❖ सिंचाई-सुविधा हेतु 3,99,899 निजी नलकूपों का संयोजन। किसानों को विद्युत आपूर्ति हेतु 2695 ग्रामीण फीडर अलग किये गये।
- ❖ सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत 22000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य।



- ❖ निजी पूंजी निवेश से 2500 मेगावाट क्षमता की तथा रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की 364 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं की स्थापना।
- ❖ झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, चित्रकूट और जालौन में सोलर पार्क की स्थापना।
- ❖ सौभाग्य योजना में 53,354 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना।
- ❖ कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट, बायो कोल, बायो डीजल/बायो एथेनॉल की स्थापना को प्रोत्साहन। गोरखपुर में कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट की स्थापना।
- ❖ नये संयोजन हेतु घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 'झटपट पोर्टल'।

❧ श्रमेव जयते ❧

- ❖ पंजीकृत श्रमिकों के पाल्यों एवं कोविड काल में निराश्रित हुए बच्चों के व्यवस्थित पठन-पाठन के लिए प्रत्येक मण्डल में सर्व सुविधायुक्त अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन।
- ❖ सेवामित्र पोर्टल पर 52,064 कुशल कामगारों का पंजीकरण।
- ❖ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनान्तर्गत 6,92,564 लाभार्थी पंजीकृत।
- ❖ अटल पेंशन योजना के माध्यम से 93 लाख से अधिक लोग लाभान्वित।
- ❖ प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत 9 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गये।
- ❖ कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में रु. 5 लाख, स्थायी दिव्यांगता पर रु. 3 लाख एवं आंशिक दिव्यांगता पर रु. 2 लाख की सहायता।
- ❖ पंजीकृत श्रमिक के दुर्घटना से मृत्यु होने पर 05 लाख का हितलाभ। सामान्य मृत्यु पर 02 लाख का हितलाभ।
- ❖ दिव्यांगता की स्थिति में योजनानुसार 02 लाख से 04 लाख तक का हितलाभ। अन्त्येष्टि हेतु रू0 25,000 का हितलाभ।
- ❖ अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना मृत्यु होने पर रू0 1 लाख का हितलाभ।



आस्था को नमन-परम्परा का सम्मान



- ❖ श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, श्री देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद, उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद, श्री विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, श्री चित्रकूट धाम तीर्थ एवं नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद उ.प्र. श्री शुक्र तीर्थ विकास परिषद का गठन ।
- ❖ श्रीकाशी विश्वनाथ धाम कॉरीडोर, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, अयोध्या दीपोत्सव, ब्रज रंगोत्सव, काशी की देव-दीपावली, नैमिष तीर्थ व शुक्र तीर्थ पुनरुद्धार, मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा का 100 साल बाद पुनः प्रतिष्ठापन, सोरों-सूकर क्षेत्र विकास आदि अद्भुत कार्य ।
- ❖ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को रु. 01 लाख प्रति श्रद्धालु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था । गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण ।
- ❖ सिन्धी समाज के सिंधु दर्शन के तीर्थ यात्रियों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से 20 हजार रुपये प्रतिव्यक्ति अनुदान दिये जाने की व्यवस्था ।
- ❖ जनपद हाथरस के 'लक्ष्मी मेला' श्री दाऊजी महाराज, जनपद अयोध्या के 'मकर संक्रान्ति मेला' एवं 'बसंत पंचमी मेला', जनपद



बुलन्दशहर के 'कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला अनूपशहर' तथा जनपद वाराणसी के देव दीपावली मेले का प्रान्तीयकरण ।

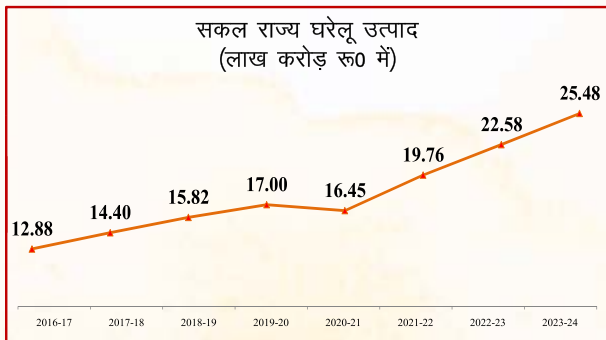
- ❖ जनपद आगरा एवं मथुरा में हेलीपोर्ट के संचालन का शुभारम्भ । लखनऊ, प्रयागराज एवं कपिलवस्तु में हेलीपोर्ट्स सेवा की सुविधा ।
- ❖ अयोध्या में विश्व स्तरीय मन्दिर संग्रहालय की स्थापना प्रक्रियाधीन ।
- ❖ जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य तपोस्थली पर वेद विज्ञान अध्ययन केन्द्र की स्थापना का निर्णय । गोरखपुर में परमहंस योगानन्द जी जन्मस्थली का पुनरोद्धार ।
- ❖ अयोध्या में भारतीय मंदिर एवं वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना का निर्णय ।
- ❖ अयोध्या शोध संस्थान का अन्तरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में उच्चीकरण ।
- ❖ प्राचीन तथा विरासत भवनों का एडोप्टिव रि-यूज के अन्तर्गत पीपीपी मॉडल पर पर्यटन हेतु विकास । मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप योजना का शुभारम्भ ।
- ❖ प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल तथा पर्यटन संभावनाओं से परिपूर्ण अल्पज्ञात स्थल का पर्यटन स्थल के रूप में विकास ।
- ❖ श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुह्य पर्यटन स्थल व बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण ।
- ❖ वृद्ध एवं विपन्न कलाकार पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के 400 से अधिक वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को पेंशन की व्यवस्था ।
- ❖ भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय को संगीत सम विश्वविद्यालय का दर्जा ।
- ❖ दीपोत्सव अयोध्या में 25,12,585 लाख से अधिक दीप प्रज्ज्वलित कराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड कायम किया ।



- ❖ राज्य सरकार द्वारा रोप-वे परियोजना पीपीपी मॉडल पर जनपद-चित्रकूट, बरसाना एवं अष्टभुजा- कालीखोह में शुरू ।
- ❖ रामायण परिपथ, बौद्ध परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, कृष्ण/ब्रज परिपथ, बुंदेलखंड परिपथ, महाभारत परिपथ, क्राफ्ट परिपथ, स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, जैन परिपथ एवं वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म परिपथ का विकास ।
- ❖ पर्यटकों की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु पर्यटन पुलिस का गठन ।
- ❖ उ०प्र० दिवस के अवसर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले महानुभावों को उ०प्र० गौरव सम्मान-2024 से सम्मानित करने का प्रावधान ।
- ❖ जनपद बलरामपुर में थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय, लखनऊ में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय का निर्माण व गोरखपुर तथा मेरठ संग्रहालय का सुदृढीकरण ।
- ❖ जनपद आजमगढ़ में हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय की स्थापना ।
- ❖ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक ग्राम बटेइवर आगरा में सांस्कृतिक संकुल का लोकार्पण ।
- ❖ सार्वजनिक रामलीला स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण ।
- ❖ जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज तथा ककरऊ कोठी में महाराणा प्रताप की 12.5 फीट अश्वारोही कांस्य प्रतिमा की स्थापना ।
- ❖ भातखण्डे सम विश्वविद्यालय को संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान ।
- ❖ सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला प्रदेश। वर्ष 2023 में कुल 48,01,27,191 पर्यटक आये, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 47,85,25,688 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 16,01,503 थी। वर्ष 2024 में जनवरी से सितम्बर तक अनुमानित कुल 47,80,74,061 पर्यटक आये, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 47,46,72,934 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 1401127 है।
- ❖ पर्यटकों की सुविधा के लिए लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू ।



रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश



उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन यू.एस. डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने के लिए नियोजित प्रयास जारी।

- ❖ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय में 9.2 प्रतिशत का योगदान।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2023-24 में GSDP बढ़कर लगभग 25.48 लाख करोड़ हो गया। चालू वित्तीय की समाप्ति पर 32 लाख करोड़ से अधिक GSDP होने का अनुमान।
- ❖ उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट। प्रदेश का यह बढ़ा हुआ राजस्व राज्य के विकास का आधार बना रहा है।
- ❖ विगत 07 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 47,118 से बढ़कर 93,514 हो गई।
- ❖ राज्य का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम एक्ट में निर्धारित सीमा 3.50 प्रतिशत के सापेक्ष 2.86 प्रतिशत रहा है।



- ❖ बैंकों का सी.डी. रेडियो मार्च, 2017 में 46.21 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2024 में 58.72 प्रतिशत हो गया है।
- ❖ पूर्व में राजस्व प्राप्तियों का लगभग 10 प्रतिशत ऋणों के ब्याज हेतु दिया जाता था। वर्ष 2023-24 में यह 8.8 प्रतिशत पर आ गया है। वर्ष 2024-25 में इसके 8.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- ❖ 2023-24 में राज्य के लिए अनुमानित GSVA 23 लाख करोड़ के सापेक्ष सकल मूल्य वर्धन 23.24 लाख करोड़ रहा
- ❖ 2023-24 में प्रदेश का कम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) लगभग 16% दर्ज किया गया है। यह स्थिति उत्साहजनक है। वर्तमान वर्ष के लिए 25% का लक्ष्य।
- ❖ बैंकिंग व्यवसाय मार्च, 2024 तक रु. 27.97 लाख करोड़ पहुंचा।
- ❖ बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से फंड आकर्षित करने में 16.2 प्रतिशत निवेश में हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर। (आर.बी.आई. बुलेटिन, अगस्त 2023)
- ❖ प्रदेश में बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) की 20036 शाखाओं, 2,74,997 बैंक मित्र एवं प्रमाणित बीसी सखी तथा 18909 एटीएम सहित कुल 3,13,942 बैंकिंग केन्द्रों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- ❖ आयकर रिटर्न फाइल करने की संख्या के पैमाने पर उत्तर प्रदेश, देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य।

**उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एटीएफ
वैट दर कई राज्यों से कम।**



अन्नदाता का उत्थान



- ❖ पी.एम. किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को रु. 79,477 करोड़ से अधिक हस्तान्तरित ।
- ❖ गन्ना किसानों को रु. 2,53,212 करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान ।
- ❖ मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर, 2019 लागू । 63 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया ।
- ❖ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 58.07 लाख किसानों को रु. 47535.09 करोड़ की क्षतिपूर्ति दी गयी ।
- ❖ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत रु. 293.69 करोड़ के वित्तीय पोषण से 34957 तालाब निर्मित । 77169 हे. सिंचित क्षेत्र में वृद्धि ।
- ❖ पी.एम. कुसुम योजना से किसानों को 76189 से अधिक सोलर पम्पों का आवंटन ।
- ❖ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 2.52 लाख किसानों को लाभार्थी कार्ड ।
- ❖ प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्रीजंक्शन योजना वन स्टाप शॉप के माध्यम से 6608 एग्रीजंक्शन की स्थापना ।



- ❖ रु. 878192.23 करोड़ फसली ऋण वितरित ।
- ❖ खेती-बाड़ी में ड्रोन के प्रयोग की शुरुआत । एफ.पी.ओ. एवं कृषि स्नातकों को ड्रोन हेतु 40-50 प्रतिशत अनुदान ।
- ❖ पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना लागू ।
- ❖ 49 जनपदों के 85710 हे. भूमि में प्राकृतिक खेती ।
- ❖ मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना में मण्डी परिषद द्वारा 79796 कृषकों को रु. 134.76 करोड़ का अनुदान ।
- ❖ 27 नवीन मण्डी स्थलों का आधुनिकीकरण । 85 नग हाट-पैठ का निर्माण ।
- ❖ 104.13 मीट्रिक टन आम का विभिन्न देशों में निर्यात ।
- ❖ मण्डियों में किसानों हेतु प्री-अराइवल ई-पास । मंडी व्यापारियों को डिजिटल पेमेन्ट की सुविधा ।

सहकार से समृद्धि

- ❖ जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से रु. 9866.70 करोड़ का अल्पकालीन ऋण वितरित ।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2024-25 में सहकारी बैंकों द्वारा रु. 226.83 करोड़ दीर्घकालीन ऋण के रूप में वितरित ।
- ❖ सहकारी समितियों द्वारा 38.17 लाख मी.टन उर्वरक तथा 36282 कुंतल बीज का वितरण ।
- ❖ 13 सहकारी बैंकों की नई शाखाएं स्थापित । पैक्स समितियों का बहुसेवा केन्द्र के रूप में विकास ।
- ❖ उ.प्र. कोऑपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों द्वारा मोबाइल एटीएम वैन का संचालन ।



सिंचाई: हर खेत को पानी

- ❖ 38 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण। 23.23 लाख हे. अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित। 44.15 लाख किसान लाभान्वित।
- ❖ 6600 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण। 3376 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण तथा 1486 राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण।
- ❖ 3 लाख 49 हजार 666 कि.मी. नहरों की सिल्ट सफाई।
- ❖ नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत रु. 14822.64 करोड़ की 67 सीवररेज परियोजनाएं स्वीकृत। 39 परियोजनाएं पूर्ण, 12 परियोजनाएं निर्माणाधीन तथा 11 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन।
- ❖ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई एवं मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में 1136917 बोरिंग / उथले नलकूप, 11003 गहरी बोरिंग एवं 29054 मध्यम बोरिंग का कार्य पूर्ण।
- ❖ अटल भूजल योजना में भू-जल प्रबन्धन हेतु 26 विकास खण्ड चयनित।
- ❖ किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प पूर्ण 14 लाख से अधिक किसान लाभान्वित।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक प्रत्येक वर्ष अनवरत ड्रेजिंग के कार्य कराए जा रहे हैं।
- ❖ ड्रेजिंग के द्वारा विभिन्न जनपदों में तटबन्धों / ग्रामों की बाढ़ से सुरक्षा के सफल परिणामों की इम्पैक्ट स्टडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कराई गई।



पशुधन संरक्षण

- ❖ निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 7707 गोआश्रय स्थलों की स्थापना तथा 16,09,557 लाख गोवंश संरक्षित ।
- ❖ 13 करोड़ 87 लाख पशुओं का टीकाकरण ।
- ❖ मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत इच्छुक कृषक/पशुपालक परिवारों को एक-एक गाय व 1500 रु. प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था ।
- ❖ मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में 2,37,369 गोवंश इच्छुक कृषक / पशुपालक परिवारों को सुपुर्द ।
- ❖ प्रदेश में पहली बार डी.बी.टी. के माध्यम से प्रति गोवंश भरण-पोषण हेतु रु. 50 प्रतिदिन की दर से गौ आश्रय स्थलों को धनराशि हस्तान्तरण ।
- ❖ निःशुल्क पशु चिकित्सकीय सहायता हेतु टोल फ्री नम्बर 1962 प्रभावी ।
- ❖ प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाये रखने के लिए 5 वर्षों में 1000 करोड़ रु. की लागत से नन्द बाबा दुग्ध मिशन का प्रारम्भ ।
- ❖ कुक्कट विकास नीति के अन्तर्गत 60 हजार पक्षी क्षमता की 4 इकाइयां व 10 हजार पक्षी क्षमता की 375 इकाइयां क्रियाशील ।
- ❖ दुग्ध संघों के सुदृढीकरण हेतु 220 समितियों का गठन एवं 450 समितियों का पुनर्गठन । ई-कॉमर्स पोर्टल से 1,22,951 उपभोक्ताओं, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं पराग मित्रों को जोड़ा गया ।
- ❖ प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उ.प्र. दुग्धशाला विकास एवं उत्पाद प्रोत्साहन नीति का प्रख्यापन ।
- ❖ मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत 1000 लाख रु. का प्रावधान ।
- ❖ मत्स्य उत्पादन हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना लागू ।
- ❖ निषाद राज बोट सब्सिडी योजनान्तर्गत 865 नाव क्रय करने के लिए अनुदान की व्यवस्था ।



उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

- ❖ कौशाम्बी में 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स', चंदौली में 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स' की स्थापना का निर्णय।
- ❖ सहारनपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स तथा वेजीटेबल्स, लखनऊ में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- ❖ लखनऊ में एग्री मॉल की स्थापना प्रक्रियाधीन।
- ❖ आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या में टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना गतिशील।
- ❖ मण्डल मुख्यालयों पर जैविक एवं प्राकृतिक उत्पादों के आउटलेट उपलब्ध।
- ❖ समस्त जनपदों में मनरेगा के अन्तर्गत 02-02 हाइटेक नर्सरी प्रक्रियाधीन।
- ❖ हापुड़ और कुशीनगर में आलू के लिए 02 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निर्माणाधीन।

जनसमस्या निवारण

- ❖ जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी व्यवस्था की गयी है। मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर आयोजित "जनता दर्शन" में प्रदेश के कोने-कोने से आये पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है।
- ❖ इन्टीग्रेटेड ग्रीवान्स रिड्रेसल सिस्टम (आई.जी.आर.एस.) के तहत दिनांक 24 जुलाई, 2024 तक प्राप्त कुल 5,03,96,306 संदर्भों में से 4,99,08,245 मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया गया।
- ❖ तहसीलों में "सम्पूर्ण समाधान दिवस" का आयोजन अब प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार तथा "थाना दिवस" दूसरे एवं चौथे शनिवार को आयोजित करते हुए प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की गई है।



स्मार्ट आत्मनिर्भर ग्राम

- ❖ 56.50 लाख से अधिक परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान करने वाला पहला प्रदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 36.15 लाख आवासों स्वीकृत, 35.77 लाख आवास पूर्ण।
- ❖ मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 2.57 लाख स्वीकृत, 2.49 लाख आवास पूर्ण।
- ❖ उत्तर प्रदेश पहला राज्य, जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के हर उस लाभार्थी जिनके पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं थी, उन्हें आवासीय पट्टा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया।
- ❖ 100 विकास खंडों का आकांक्षात्मक विकास खंड के रूप में चयन। विकास कार्यों की सतत निगरानी के लिए 'मुख्यमंत्री फेलो' की तैनाती।
- ❖ गांव के विकास में आम जन की प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'मातृभूमि योजना' संचालित।
- ❖ अमृत सरोवर के निर्माण में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम।
- ❖ मनरेगा में 212.62 करोड़ मानव दिवस सृजित।
- ❖ अप्रैल, 2017 से अब तक 28538 किमी. लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण किया गया।
- ❖ अप्रैल, 2017 से अब तक 22286 किमी. लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।
- ❖ प्रतिवर्ष औसतन 4076 किमी. मार्गों का नव निर्माण एवं 3184 किमी. मार्गों का चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण।
- ❖ 09 किमी. प्रतिदिन की औसत से सड़कों का चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण, 11 किमी. प्रतिदिन की औसत से मार्गों का नवनिर्माण।



- ❖ 46 नये राष्ट्रीय मार्ग (लम्बाई 4115 कि.मी.) घोषित। 70 नये राज्य मार्ग (लम्बाई 5604 कि.मी.) घोषित। 57 नए प्रमुख जिला मार्ग (लम्बाई 2831 किमी.) घोषित।
- ❖ प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित ग्राम सचिवालय के प्रतिदिन संचालन व सफल क्रियान्वयन हेतु पंचायत सहायक/ एकाउन्टेन्ट कम डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की तैनाती।
- ❖ ऑपरेशन कार्याकल्प के अंतर्गत प्रदेश में 83,066 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुरक्षण व मरम्मत, 24,580 आंगनबाड़ी भवनों का सुदृढीकरण, 79,718 बाल मैट्रिक शैचालयों का पुनरुद्धार।
- ❖ ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की पद पर रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार/ आश्रित के सहायतार्थ पंचायत कल्याण कोष की स्थापना।
- ❖ बी.सी. सखियों द्वारा रु. 26481 करोड़ से अधिक का लेनदेन और लगभग रु. 71.21 करोड़ का लाभांश अर्जित किया गया।
- ❖ 10500 विद्युत सखियों द्वारा रु. 1120 करोड़ का विद्युत बिल कलेक्शन सम्बन्धी कार्य किया गया, जिससे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं (विद्युत सखियों) को रु. 14.60 करोड़ कमीशन प्राप्त हुआ।
- ❖ स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों द्वारा प्रदेश में 2510 उचित दर की दुकानों का संचालन किया जा रहा है।
- ❖ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास प्लस से लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश।
- ❖ वर्ष 2024 तक पाइप पेयजल योजना द्वारा 'हर घर जल' उपलब्ध कराने का लक्ष्य।



- ❖ अटल भूजल योजना में प्रदेश के 26 विकास खंड भूजल प्रबंधन में सुधार लाये जाने के उद्देश्य से चयनित प्रदेश की 550 ग्राम पंचायतों में वॉटर सिक्योरिटी प्लान विकसित।
- ❖ पी.एम. स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 86,62,801 परिवारों को घरौनी।
- ❖ अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्रदेश स्तर पर एंटी भू- माफिया टास्क फोर्स का गठन।
- ❖ एंटी भू-माफिया के अन्तर्गत 66,831.45 हे. क्षे. अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त। 1573 अतिक्रमणकर्ता भू-माफिया के रूप में चिन्हित, 213 जेल निरुद्ध।

❧ 100% ODF+ राज्य ❧

- ❖ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश 100 प्रतिशत ओडीएफ+ राज्य घोषित।
- ❖ 95,767 गांवों ने ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ अपने को ODF+ घोषित किया।
- ❖ विगत 9 महीनों में 80,000 से अधिक गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त किया।
- ❖ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रथम चरण में 2.18 करोड़ इज्जत घर/ व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण सर्वाधिक शौचालय निर्माण के साथ देश में प्रथम।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण।



❧ वंचित को वरीयता ❧

- ❖ सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लागू। 03 वर्षों में 700+ युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल।
- ❖ निराश्रित महिला, वृद्धावस्था तथा दिव्यांगजन पेंशन के अन्तर्गत 97.20 लाख लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रु. पेंशन।
- ❖ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 4, 17, 232 जोड़ों का विवाह। अनुदान राशि 35 हजार से बढ़कर रु. 51 हजार हुई।
- ❖ ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम की सुविधा उपलब्ध।
- ❖ कोविड काल अथवा पूर्व में निराश्रित बच्चों व किशोरों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन।
- ❖ पूर्वदशम अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में 32,49,854 छात्रों को रु. 708.49 करोड़ छात्रवृत्ति दी गयी।
- ❖ दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के तहत 89,31,203 छात्रों को रु. 9,662.25 करोड़ छात्रवृत्ति दी गयी।
- ❖ 2017-18 से 2023-24 तक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में पिछड़े वर्ग के 63,55,798 छात्र/छात्राओं को लगभग रु. 1,297.09 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित।
- ❖ दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अन्तर्गत 1,20,25,019 छात्र/छात्राओं को रु. 5,788.14 करोड़ हस्तांतरित।
- ❖ पूर्वदशम सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति योजना के तहत 8,58,750 छात्रों को रु. 221.95 करोड़ छात्रवृत्ति दी गयी।
- ❖ दशमोत्तर सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति योजना के तहत 48,13,347 छात्रों को रु. 5,499.86 करोड़ छात्रवृत्ति दी गयी।
- ❖ शादी अनुदान योजना में 4,75,567 लाभार्थियों को रु. 951.13 करोड़ हस्तांतरित।



- ❖ हज 2023 में 24960 यात्री हज यात्रा पर भेजे गये। इनकी सहायता के लिए 30 हज सेवकों को भी भेजा गया।
- ❖ अनुदानित मदरसों में एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम लागू।
- ❖ 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 1,000 रु. भरण-पोषण अनुदान।
- ❖ कुष्ठावस्था पेंशन योजना में अनुदान राशि रु. 2500 से बढ़ाकर रु. 3000 प्रति माह की गयी।
- ❖ दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण के साथ कृत्रिम अंग देने की व्यवस्था।
- ❖ दिव्यांगजन राज्यस्तरीय पुरस्कार की श्रेणियां 3 से बढ़ाकर 12 की गयी, पुरस्कार की धनराशि रु. 5000 से बढ़ाकर रु. 25000 की गयी।

❧ खाद्य एवं रसद ❧

- ❖ प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न, 1 कि.ग्रा. दाल/साबुत चना, 1 कि.ग्रा. आयोडाइज्ड नमक, 1 कि.ग्रा. रिफाइनड ऑयल का निःशुल्क वितरण। इसके अलावा अन्त्योदय राशन कार्डधारकों के लिए प्रति माह 1 कि.ग्रा. चीनी का निःशुल्क वितरण।
- ❖ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.75 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन। होली व दीपावली पर 02 निःशुल्क एल.पी.जी. सिलेंडर का वितरण।
- ❖ बेघरों तथा कचरा उठाने वाले नागरिकों को राशन कार्ड की सुविधा।
- ❖ डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था। उचित दर की दुकानें बर्नी कॉमन सर्विस सेन्टर।



- ❖ रबी विपणन वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक 233.99 लाख मी. टन गेहूं की खरीद कर रु. 43,416 करोड़ का किसानों को भुगतान।
- ❖ खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक 399.59 लाख मीट्रिक टन धान क्रय कर रु. 75,692 करोड़ का भुगतान।
- ❖ खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 से बाजरा खरीद प्रारम्भ। 75,434 किसानों से 3,98,475.89 मी.टन बाजरा की खरीद कर 98,193.59 लाख का भुगतान।
- ❖ 2023-24 में पहली बार ज्वार की खरीद की गई। 2787 किसानों से 13340 मी.टन ज्वार खरीद 422.76 लाख का भुगतान।
- ❖ खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक 27,818 किसानों से 1,18,767.99 मी.टन मक्का की खरीद कर 22,005.21 लाख का भुगतान।

**2015-16 और 2019-21 के बीच उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दंश से मुक्त हुए।
(नीति आयोग की रिपोर्ट 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक-एक प्रगति समीक्षा 2023')**



सशक्त नारी-समृद्ध समाज

- ❖ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 22.12 लाख, निराश्रित महिला पेन्शन योजना में 30.98 लाख, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) में 18,990 तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) में 53,610 पात्र लाभान्वित ।
- ❖ 2 लाख से अधिक महिलाएं पी.एम. स्वनिधि योजना से लाभान्वित ।
- ❖ उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 873534 समूहों, 57482 ग्राम संगठनों एवं 3137 संकुल स्तरीय संघों का गठन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र की 95 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया ।
- ❖ महिला स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 2510 उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया गया ।
- ❖ प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना से 60 लाख माताएं लाभान्वित ।
- ❖ 39561 बी.सी. सखी ने कार्य करते हुए रु. 31626 करोड़ का लेनदेन किया । बी.सी. सखियों ने रु. 85.81 करोड़ अर्जित कर लाभांश प्राप्त किया ।
- ❖ वन स्टाफ सेंटर से अब तक 2.03 लाख महिलाएं लाभान्वित ।
- ❖ 189 निकायों में महिलाओं के लिए 1100 पिक शौचालयों का निर्माण ।
- ❖ 181-महिला हेल्पलाइन योजना के अंतर्गत 7.17 लाख महिलाओं को सहायता ।
- ❖ आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्री-स्कूल के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है ।
- ❖ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि । 3.73 लाख महिलाएं लाभान्वित ।



- ❖ आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार योजनांतर्गत पोषाहार वितरण में बायोमैट्रिक प्रणाली लागू।
- ❖ जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने 6,591 आंगनबाड़ी केन्द्र गोद लिये।
- ❖ कुपोषण एवं पोषण स्थिति की पहचान हेतु सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए चार प्रकार के ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस एवं मोबाइल फोन की उपलब्धता।
- ❖ प्रदेश में 0 से 5 वर्ष के बच्चों में स्टंटिंग (उम्र के सापेक्ष कम लंबाई) की दर में 6.5 प्रतिशत की गिरावट (NHFS-4 व 5)
- ❖ प्रदेश में 0 से 5 वर्ष के बच्चों में अंडरवेट (उम्र के सापेक्ष कम वजन) की दर में 7.5 प्रतिशत की गिरावट (NFHS-4 व 5)
- ❖ गर्भवती महिलाओं के एनीमिया की दर में 5.1 प्रतिशत पॉइंट की कमी आई।
- ❖ सतत प्रयासों से महिला-पुरुष लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार। प्रति 1000 पुरुष के सापेक्ष 1017 महिलाएं।
- ❖ 60 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पुष्टाहार का वितरण।
- ❖ मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर एवं नवजात मृत्युदर में अभूतपूर्व गिरावट।
- ❖ संस्थागत प्रसव 84 प्रतिशत से अधिक।



बेहतर होतीं स्वास्थ्य सुविधाएं

- ❖ हर गरीब परिवार को 5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा सुरक्षा कवच।
- ❖ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1.31 करोड़ परिवारों के लगभग 9 करोड़ लाभार्थी आच्छादित।
- ❖ 8.43 लाख परिवारों के 42.19 लाख लोग मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित।
- ❖ अंत्योदय कार्ड धारक 40.79 ब्लॉक परिवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सम्मिलित।
- ❖ उ० प्र० भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत एवं सूचना विभाग में पंजीकृत 11.65 लाख परिवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सम्मिलित।
- ❖ आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश में 5834 अस्पताल (2949 सरकारी, 2885 निजी) सूचीबद्ध। अब तक 53 लाख 93 हजार लोग लाभान्वित।
- ❖ एडवांस लाइफ सपोर्ट सेवा की 250, नेशनल एम्बुलेंस सेवा की 2270 एवं 108 सेवा के तहत 2200 एम्बुलेंस संचालित।
- ❖ मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में अब तक 13.31 करोड़ मरीजों का उपचार।
- ❖ राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स हेतु पं. दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना प्रारम्भ।
- ❖ हेल्थ ए.टी.एम. का शुभारम्भ। प्रदेश के पी.एच.सी. में हेल्थ ए.टी.एम. की स्थापना।
- ❖ 5000 नये स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना।
- ❖ प्रदेश में दवाओं की पारदर्शी व गुणवत्तापरक खरीद के लिए उ.प्र. मेडिकल सप्लाय कॉरपोरेशन की स्थापना।



- ❖ प्रदेश के दूर दराज के मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा टेली कन्सल्टेशन की व्यवस्था। 3.46 करोड़ लोग लाभान्वित।
- ❖ 72 जनपदों में डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध। 25 हजार से अधिक लोग लाभान्वित।
- ❖ निःशुल्क डायग्नोस्टिक सेवाओं के अन्तर्गत 70 जनपदों में सी0टी0 स्कैन सेवा उपलब्ध। 29 लाख से अधिक लोग लाभान्वित।
- ❖ प्रदेश के 51 जिला चिकित्सालयों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। यह संख्या देश में सर्वाधिक है।
- ❖ 22681 आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेण्टर क्रियाशील।
- ❖ रोगों की स्थिति की जानकारी तथा रोकथाम हेतु यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस पोर्टल के रूप में एक अभिनव प्रयोग।
- ❖ अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता और कार्यक्षमता की जानकारी व निगरानी प्राप्त करने के लिए 'केयर मॉडल' लागू।
- ❖ गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड के लिए ई-रूपी वाउचर का उपयोग।
- ❖ विशेष संचारी रोग नियंत्रण/दस्तक अभियान के तहत एईएस-जेई वायरस के खिलाफ सघन अभियान।
- ❖ एईएस के रोगियों की मृत्यु दर में 98 प्रतिशत की कमी, जेई के रोगियों की मृत्यु 97 प्रतिशत तक कम करने में सफलता।
- ❖ राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वित। प्रत्येक माह की 15 तारीख को टीबी, कालाजार, फाइलेरिया, कुष्ठ रोग के लिए सभी 'हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में एकीकृत निक्षय दिवस' मनाया जा रहा है।
- ❖ फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 'प्रमोट फार्मा संस्था' की स्थापना।



सुलभ चिकित्सा शिक्षा

- ❖ 44 राजकीय मेडिकल कॉलेज और 35 निजी मेडिकल कालेजों सहित 79 मेडिकल कॉलेज संचालित।
- ❖ बिजनौर, बुलन्दशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, औरैया, चन्दौली, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी जनपद के स्वाशाषी मेडिकल कॉलेजों तथा पीपीपी मोड के महाराजगंज, शामली और सम्भल स्थित मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रवेश प्रारम्भ।
- ❖ 16 असेवित जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए पीपीपी मोड की नीति।
- ❖ लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर एवं रायबरेली में एम्स की स्थापना।
- ❖ वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में 5250 एम.बी.बी.एस. सीट तथा निजी क्षेत्र में 6550 एम.बी.बी.एस. सीट उपलब्ध। पीपीपी मोड के तीन नये मेडिकल कालेजों में 350 सीटें उपलब्ध।
- ❖ सरकारी क्षेत्र में एम.डी/एम.एस/डिप्लोमा सीटों की संख्या 900 से बढ़कर 1871 हो गयी। निजी क्षेत्र में कुल पी.जी. सीटें 2100।
- ❖ वर्तमान में सुपर स्पेशियलिटी की कुल 250 सीट उपलब्ध।
- ❖ कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, लखनऊ में सेंटर फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एण्ड रिसर्च फॉर कैंसर स्थापित।
- ❖ मिशन निरामया: के अन्तर्गत नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थाओं की गुणवत्ता सुधार हेतु अनेक कार्यक्रमों का संचालन। मेंटॉर-मेंटी मॉडल लागू।



- ❖ नर्सिंग में 7000 सीट्स तथा पैरामेडिकल में 2000 सीटों की वृद्धि ।
- ❖ बंद पड़े 35 एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों को पुनः शुरू किया गया ।
- ❖ महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना । प्रदेश में आयुष बोर्ड के गठन का निर्णय ।

नवाचारी-नवोन्मेषी शिक्षा



- ❖ स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम (स्कूल आएँ हर दिन) जैसे अभिनव प्रयासों से 40 लाख अतिरिक्त बच्चों का नामांकन । ड्राप आउट दर में उल्लेखनीय गिरावट ।
- ❖ परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफार्म, स्वेटर, जूते-मोजे एवं स्कूल बैग, स्टेशनरी उपलब्ध कराने हेतु अभिभावकों के बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से प्रति छात्र रु. 1200 ऑनलाइन हस्तान्तरित ।
- ❖ ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तीकरण ।
- ❖ बेसिक शिक्षा की परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2,09,863 लाख शिक्षकों को टैबलेट वितरण ।



- ❖ गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का शुभारम्भ ।
- ❖ 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ ।
- ❖ 57 जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों के निर्माण की कार्य योजना तैयार ।
- ❖ पी.एम. श्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए ग्रीन विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय ।
- ❖ असेवित क्षेत्रों में 39 नवीन हाईस्कूल और 14 नवीन इण्टर कालेजों का निर्माण ।
- ❖ 07 नये केन्द्रीय विद्यालयों हेतु भूमि की व्यवस्था ।
- ❖ स्कूल मैपिंग के लिए 'पहुंच', करियर काउन्सिलिंग के लिए 'पंख', ई-लाइब्रेरी के लिए 'प्रज्ञान', अनुश्रवण के लिए 'परख', कौशल प्रशिक्षण के लिए 'प्रवीण', विद्यालयों के लिए 'पहचान' एवं संसाधन मैपिंग के लिए 'प्रोजेक्ट अलंकार' पोर्टल का विकास ।
- ❖ 'राज्य अध्यापक' व 'मुख्यमंत्री अध्यापक' पुरस्कार हेतु नवीन मानक विकसित ।
- ❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की कार्य योजना विकसित करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी ।
- ❖ पी.एम. ई-विद्या चैनल तथा दीक्षा पोर्टल पर विषयवार शैक्षिक वीडियो तथा परिषद की वेबसाइट पर ई-पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता ।
- ❖ 11 नवीन तथा 05 नवीन आवासीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का निर्णय ।
- ❖ रोजगारपरक शिक्षा हेतु उ.प्र. माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा 04 डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ ।
- ❖ माध्यमिक शिक्षा विभाग में अज्ञासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु विशेष नीति का निर्धारण ।



- ❖ प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल जनपद गोरखपुर में स्थापना एवं संचालन।
- ❖ वर्तमान में 22 राज्य विश्वविद्यालय, 44 निजी विश्वविद्यालय, 171 राजकीय महाविद्यालय, 331 आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, 01 डीम्ड तथा 01 मुक्त विश्वविद्यालय एवं 7,372 स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में 52.28 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत।
- ❖ मां झाकुंभरी वि.वि. सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य वि.वि. अलीगढ़ और महाराजा सुहेल देव राज्य वि.वि. आजमगढ़ की स्थापना।
- ❖ माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मीरजापुर, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल, गुरु जंभेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद तथा कुशीनगर जनपद में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास।
- ❖ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित करने का निर्णय।
- ❖ 15 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत। 08 अन्य निजी विश्वविद्यालय के संबंध में आशय पत्र निर्गत करने की कार्यवाही।
- ❖ लखनऊ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी को NAAC मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त।
- ❖ उच्च शिक्षा निदेशालय परिसर में e-Content रिकॉर्डिंग स्टूडियो की स्थापना।
- ❖ संस्कृत विद्यालय एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति में 24 साल बाद बढ़ोत्तरी का निर्णय।



- ❖ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- ❖ स्टार्ट अप नीति के तहत प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं ए.के.टी.यू. के संस्थानों में 15 इन्क्यूबेशन सेन्टर की स्थापना।
- ❖ मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर को NAAC मूल्यांकन में A ग्रेड।
- ❖ राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में न्यू एज कोर्स डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण संचालित।
- ❖ 89 पॉलीटेक्निक में लैंग्वेज लैब तथा राजकीय पॉलीटेक्निक में 43 नवीन स्मार्ट क्लास रूम स्थापित।

❧ खेल के साथ-साथ रोज़गार ❧

- ❖ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना।
- ❖ उत्तर प्रदेश की नयी खेल नीति-202 को मंजूरी। राज्य खेल प्राधिकरण की होगी स्थापना।
- ❖ अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर नियुक्ति।
- ❖ ओलम्पिक गेम्स (एकल वर्ग) में स्वर्ण पदक पर 06 करोड़ रुपये, रजत पदक पर 04 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक जीतने पर 02 करोड़ रुपये के पुरस्कार की व्यवस्था।
- ❖ ओलम्पिक गेम्स (टीम गेम्स) में स्वर्ण पदक पर 03 करोड़ रुपये, रजत पदक पर 02 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक जीतने पर 01 करोड़ रुपये का पुरस्कार।



- ❖ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 03 करोड़ रुपये, रजत पदक पर डेढ़ करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक जीतने पर 75 लाख रुपये का प्रोत्साहन ।
- ❖ कॉमनवेल्थ गेम्स अथवा विश्वकप से जुड़ी प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक पर डेढ़ करोड़ रुपये, रजत पदक पर 75 लाख रुपये तथा कांस्य पदक जीतने पर 50 लाख रुपये का पुरस्कार ।
- ❖ ओलम्पिक गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रतिभाग किये जाने पर प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 लाख रुपये और कॉमनवेल्थ गेम्स तथा एशियन गेम्स में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 05-05 लाख रुपये का नकद पुरस्कार ।
- ❖ मेजर ध्यानचन्द डिजिटल हॉकी संग्रहालय का उद्घाटन ।
- ❖ एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना ।
- ❖ एक जिला-एक खेल योजना अन्तर्गत 'खेलो इण्डिया सेंटर' स्थापित कर प्रदेश के 75 जिलों में से 69 जनपदों में प्रशिक्षण संचालित ।
- ❖ ग्रामीण स्तर पर 82 स्टेडियम स्थापित ।
- ❖ वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना प्रक्रियाधीन ।
- ❖ 25,000 पी.आर.डी. जवानों को प्रत्येक माह इयूटी ।



आत्मनिर्भर होते युवा

**प्रदेश की बेरोजगारी दर फरवरी, 2016 में 18 प्रतिशत थी।
वर्तमान में 2.4 प्रतिशत है।**

- ❖ निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न आयोगों एवं भर्ती बोर्ड द्वारा 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी।
- ❖ 1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी।
- ❖ रोजगार मिशन समिति का गठन प्रक्रियाधीन।
- ❖ अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए UPPSC में एकल अवसरीय रजिस्ट्रेशन (OTR) व्यवस्था लागू।
- ❖ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन एवं संचालन।
- ❖ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में प्राप्त निवेश प्रस्तावों से 1 करोड़ 10 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार व सेवायोजन के अवसर।
- ❖ एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में 1,10,72,209 रोजगार सृजित।
- ❖ एक जनपद-एक उत्पाद योजनान्तर्गत 1,35,250 व्यक्तियों को रोजगार।
- ❖ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 20,049 युवा लाभान्वित तथा रोजगार के 1,60,392 अवसरों का सृजन।
- ❖ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 2,18,412 पात्र लाभान्वित।
- ❖ स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना में 20.05 लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट/ स्मार्टफोन का वितरण। 2 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य।



- ❖ प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स संचालित ।
- ❖ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 22,839 इकाइयां स्थापित करते हुए 1,82,712 लोगों को रोजगार ।
- ❖ मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में 01 लाख से अधिक युवाओं का उद्योगों एवं अधिष्ठानों में पंजीकरण एवं प्रशिक्षण ।
- ❖ आई.टी.आई व कौशल विकास मिशन में 25 लाख से अधिक युवा विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित । 10.20 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार ।
- ❖ इण्डस्ट्री 4.0 के अनुरूप नये उभरते क्षेत्रों जैसे आर्टीफिशियल इन्टेलीजेंस, एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (रोबोटिक्स) इत्यादि में छात्रों को प्रशिक्षण ।
- ❖ ऋण प्रवाह अभियान के अन्तर्गत रु. 37,000 करोड़ का ऋण वितरित ।
- ❖ स्वरोजगार संगम कार्यक्रम में 22,319 युवा प्रशिक्षित ।